>

Title: Need to determine appropriate remunerative price for onion in the country.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, मैं महाराष्ट्र के डिंडोरी क्षेत्र से आता हूं और ज्यादातर मेरे क्षेत्र में प्याज का उत्पादन होता है, जिसे मराठी में कांदा बोलते हैं। गवर्नमेंट को प्याज को जन आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाने से पहले सार्वजनिक डिस्कशन करने की जरूरत थी, जन आवश्यक याने प्याज जो खाता नहीं, वह तो कभी मरता नहीं, इसका मतलब प्याज जन आवश्यक चीज़ तो नहीं है। जब वह जन आवश्यक नहीं है तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कैसे?

प्याज की एक तो आयु मर्यादा बहुत ही कम होती है। वह जल्द ही खराब होने वाली चीज़ है। वैसे प्याज की खेती करना आजकल किसानों को बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसे थोड़ा अलग नज़रिये से देखना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि मार्केट में प्याज की कीमतें बहुत ही आसमान छू रही हैं, फिर भी मेरी विनती रहेगी कि प्याज को एसेंशियल कमोडिटी से निकालना चाहिए।

आज हमारे यहां इसके एक्सपेंडीचर में पौधा तैयार करने की लागत, बोने और फसल कटाई तक, भण्डारण और पाउडर का खर्चा करीबन एवरेज 70 हजार रुपये आता है और सब खर्चे मिलाकर उनको कभी-कभी प्रोफिट पांच हजार रुपये या दस हजार रुपये मिलता है। इसलिए बहुत सारे किसान आज भी हमारे यहां आत्महत्या करते हैं।

मेरी सरकार को एक और भी विनती है कि जो निर्यात शुल्क 500 डॉलर तक तय किया है, उसको शून्य करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि हर किसान प्याज लगा सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे मंडी में प्याज की किल्लत महसूस न हो। जिससे किसान और ग्राहक दोनों संतुष्ट रह सकें।

*t32

Title: Need to set up a Steel factory by Steel Authority of India Limited in Tikamgarh Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के छतरपुर जिले में बिजावर बकस्वाहा तथा बड़ामलहरा क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का विशाल भंडार है। सैकड़ों वर्ष पूर्व से यहां पर लौह अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता रहा है। प्राचीन काल में बिजावर में इस्पात की भट्टी चलती थी। पहाड़ों में आज भी उसके चिन्ह देखने को मिलते हैं। सर्वे की जानकारी के अनुसार वर्तमान में देश के जो इस्पात संयंत्र हैं, उनके समीप जो लौह अयस्क है, उससे 3 से 4 प्रतिशत से अधिक मात्रा में छतरपुर के पहाड़ों में जो अयस्क है, उसमें लोहा है, जो अधिक गुणवत्ता वाला है। किंतु पूर्व में विद्युत की कमी तथा रेलवे में सुविधा न होने से यहां इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं हो सका है। आज इस क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा विद्युत संयंत्र लगाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा रेल लाइन भी ललितपुर से छतरपुर तक बिछायी जा चुकी है जिसके कारण जिले में इस्पात संयंत्र स्थापित करना आसान हो गया है। बुंदेलखंड देश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसके औद्योगिक विकास के लिए उक्त संयंत्र की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करायी गयी इन्वेस्टर्स मीट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर कर रूचि प्रदर्शित की गयी थी। अतः सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र इस दिशा में कार्यवाही कर इस वर्ष की कार्य योजना में शामिल कर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा छतरपुर में स्टील कारखाना लगाये जाने की पहल प्रारंभ की जाए, ।

*t33

Title: Need to revive Maize Research Centre in Begusarai Parliamentary Constituency of Bihar.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : महोदय, मैं बिहार के बेगूसराय लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। 23 वर्ष पहले बेगूसराय जिले के कुशमाहोत, जो दुनिया की सबसे उर्वर काली जमीन है, वहां तत्कालीन केन्द्र सरकार ने मक्का अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की थी। 23 वर्षों में इस मक्का अनुसंधान केन्द्र ने अपने अनुसंधान के पेट से एक भी अनुसंधान के बीज की डिलीवरी नहीं दी है। वहां पदाधिकारी हैं, कर्मचारी भी हैं, हमारे पुरखों ने सैंकड़ों एकड़ जमीन दी है और आज वह मृत पड़ा हुआ है।

यह खुशी की बात है कि इस देश के राजनीतिक रंगमंच पर एक अद्भुत व्यक्तित्व का उपस्थापन हुआ है और जनता के बीच में अपेक्षाएं और आशाएं बढ़ी हैं। वर्तमान सरकार जिनके कृषि मंत्री, कृषि संस्कृति और संस्कार के बेटे हैं। हम उनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि अनुसंधान केन्द्र में जो अनियमितताएं हुई हैं, लूटपाट हुई है और जो भ्रष्टाचार का आलम छाया रहा है, वे इसकी जांच करें और इसके विस्तार के लिए इसे पुनर्जन्म देने के लिए आवश्यक और अपेक्षित कार्यवाही करें। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

*t34

Title: Need to review the Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM).

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेहरू पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत शहरी गरीब के लिए घरों के निर्माण की योजना बनती है। इसके लिए केंद्र और राज्य से निधि प्राप्त होती है। केंद्र से पचास टका और राज्य से तीस टका प्राप्त होता है। जो योजना लाभार्थी है, वह दस टका देता है। मैं इस योजना की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र के मावल क्षेत्र से हूं। पिंपरी चिंचवाड़ा कारपोरेशन को जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत 2050 मकानों को लिए करीब 6,500 करोड़ रुपए मिले हैं। इस योजना के अंतर्गत जो मकान बने हैं, गरीबों के लिए जो घर बने हैं, वे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो जगह आती है उसमें बने हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि एक आदमी कोर्ट में गया। कोर्ट ने जितने भी मकान बने हैं उन पर स्टे लगाया। केन्द्र अगर ऐसी योजना को इतनी बड़ी निधि देती है तो क्या कुछ कागज नहीं देखती है? केन्द्र को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव को ठीक से देख ले।

*t35

Title: Regarding crisis in Iraq.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, मैं मूल रूप से इराक और सीरिया की स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हम लगातार इसे देख रहे हैं। पिछले दो महीनों से एवं इसके पहले जो स्थिति इराक और सीरिया में उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण वहां के सामान्य नागरिकों, चाहे वे किसी भी समाज से संबंधित हों, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते हैं, को बर्बरता और क्रूरता का शिकार होना पड़ रहा है। दुनिया में जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह चिंता का विषय है। भारत की आबादी 1.25 करोड़ है। यहां के लोग दुनिया भर में काम करने जाते हैं। जिस प्रकार की घटना केरल की नर्सों के साथ हुई और मौसूल एवं तिरकित में रह रहे लोगों और परिवारजनों के साथ विदेश मंत्रालय का लगातार संपर्क होता रहा। वे कोशिश करते रहे कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। हमें यह भी याद रखना होगा कि जिन्हें हम सुरक्षित ले कर आए हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां जाने एवं रोजगार पाने के लिए कर्ज लिए थे। उन्होंने ट्रैवेल एजेंट को पैसे दिए थे। जो वहां रोजगार दिलाते हैं उनको पैसे दिए थे। बहुत सारे लोग लौट कर यहां आए हैं। कुछ नर्सेज और वहां काम करने गए कुछ लोग लौट कर नहीं आ पाए हैं।

सभापति महोदय, चिंता इस बात की है कि मौसूल और तिरकित में अभी भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लेबर्स फंसे हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से भरपुर प्रयास किया है। मैं सुषमा स्वराज जी, अपनी सरकार को और तमाम डिप्लोमैटिक मिशन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि भारत की कुछ एजेंसियों ने वहां जा कर उनसे संपर्क साधा है और भारत के नागरिकों को वापस ले कर आए हैं। यह एक मानवीय विषय है। हमारे लोग दुनिया भर में जा कर काम करते हैं, उनको पूरी दुनिया का सहयोग मिला है लेकिन चिंता यह है कि जिस प्रकार से यहां की घटनाएं हो रही हैं, जो लोग सामान्य रूप से वीडियो और एम.एम.एस देखते हैं, जिस क्रूरता के साथ वहां पर आपसी संघर्ष हो रहे हैं, उन वीडियो को जिनका प्रसारण पूरी दूनिया में हो रहा है, अगर देखा जाए तो उस क्रूरता का दूसरा स्वरूप हम कहीं नहीं देख सकते हैं।

महोदय, जो अस्थिरता इराक और सीरिया में उत्पन्न हो गई है, यह चिंता का विषय है। जो भी ताकते इसमें लगी हुई हैं, किन के बीच में झगड़ा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इससे पूरे दुनिया में एक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न होगा। महोदय, मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं, यह आग्रह करना चाहता हूं कि मिडल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बन चुकी है, उसमें सुधार आए। विशेषकर, जो नागरिक अभी भी इराक या अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए सरकार ने पहल की है। मैं सरकार को बधाई देने के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो शेष लोग आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। जिन लोगों को वापस लाया गया है, सरकार विशेष निधि से उन लोगों को कर्ज चुकाने और नए व्यवसाय करने या अतिरिक्त व्यवसाय देने की व्यवस्था करे। चाहे वे केरल के लोग हों, वे गुजरात के लोग हों, वे बिहार के लोग हों या वे मध्यप्रदेश के लोग हों, सरकार संवेदना के साथ उनकी समस्याओं पर विचार करें।

HON. CHAIRPERSON :

*m02 Shri Shivkumar Udasi and

*m03 Dr. Virendra Kumar are allowed to associate with the matter raised by Shri Rajiv Pratap Rudy.

*t36

Title: Need to set up a marine training academy in Gujarat.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैंने पिछली लोक सभा में इस विषय को लगातार उठाया था। इस विषय को सदन में बार-बार उठाने के बाद के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। गुजराती में एक कहावत है **:** "बेश कानें वात अथडातीनथी" आज मैं फिर से इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। गुजरात में 1663 किलोमीटर की सामुद्रिक सीमा पड़ती है और वर्षों से गुजरात मरीन टेरर्स से जूझ रहा है। राज्य के इतने लम्बे संवेदनशील सामुद्रिक सीमा को मद्देनजर रखकर कोस्टल सिक्युरिटी फेज़ वन का काम मरीन पुलिस स्टेशन, चैक पोस्ट तथा आउट पोस्ट स्थापित किए हैं। 12 और 5 टन की बोट द्वारा कोस्टल पैट्रोलिंग की जा रही है। समग्र भारत भर में फेज़ वन का कार्य पूरा करने में गुजरात अव्वल नम्बर पर है। फेज़ टू का काम अब शुरू हो गया है। सामुद्रिक सीमा के विस्तारों में कार्य करने और ऑफशोर पैट्रोलिंग करने के लिए अलग किस्म का अनुभव जरूरी है। उनके बारे में खास प्रकार के प्रशिक्षण वाले कर्मचारियों, कोस्टल पुलिस स्टेशनों में ड्यूटी बजाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप मूलभूत प्रशिक्षण देने के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाने तथा पैट्रोलिंग वोट के ऑपरेशन और मेनटेनैंस के बारे में स्पैशल कोर्स चलाने की अति आवश्यकता है जिसके लिए अलग प्रकार की तालीम, शिक्षा की जरूरत है।...(व्यवधान)

मैं एक बात कहना चाहती हूं। मरीन पुलिस एकाडमी का निर्माण करने के लिए गुजरात सरकार ने कुछ खास पुलिस अधिकारियों की टीम को राज्य की सामुद्रिक सीमा का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। जियोग्राफिकली और ट्रेनिंग के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं को मद्दे नजर रखकर गुजरात के लिए पोरबंदर-मरीन पुलिस एकाडमी के लिए अनुकूल है। राज्य सरकार ने इस एकाडमी के लिए केन्द्र की जरूरत के मुताबिक जामनगर जिले में 250 एकड़ जमीन निशुल्क देने के लिए सैद्धांतिक सहमति जताई है। इससे हम भारत सरकार को भी अवगत कराते हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मरीन टेरर्स से जूझ रहे गुजरात और देश की सुरक्षा की परिपूर्ति हेतु गुजरात राज्य में मरीन ट्रेनिंग एकाडमी की स्थापना की मंजूरी जल्द से जल्द दी जाए तथा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ठोस कदम उठाए जाएं।

*t37

Title: Request to grant compensation to five applicants died during physical test for police recruitment in Mumbai.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति जी, मुम्बई में...(व्यवधान) Sir, Members are disturbing me and asking about the allotment of houses. ...(व्यवधान) मुम्बई में दो सप्ताह पहले जिस प्रकार की परिस्थिति में 20 साल, 22 साल के पांच नौजवानों की मृत्यु हुई, मैं इसके प्रति आपका और आपके माध्यम से सरकार, समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे जवान किसलिए मुम्बई आए थे। कोई गड़चिरोली आदिवासी क्षेत्र से आया था, कोई चंद्रपुर के पिछड़े क्षेत्र से आया था। गृह मंत्रालय की पुलिस की भर्ती में वे परीक्षा देने के लिए, नौकरी के लिए आए थे। मुम्बई जैसे शहर में दिन-दहाड़े साढ़े बारह बजे, डेढ़ बजे, दो बजे, तीन बजे सरकार और गृह मंत्रालय उनकी फिजिकल टैस्ट की परीक्षा मई और जून महीने में, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, एक ही दिन पांच लोगों की मृत्यु नहीं हुई। पहले एक की मृत्यु, दो-तीन दिन के बाद दूसरा, चार दिन बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन वह सरकार कुभंकरण की सरकार रही। उन्होंने पांच लोगों की मृत्यु तक कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, पूरा समाज उनके प्रति सरकार, गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर को रोज कह रहा था कि फिजिकल टैस्ट रोको। इनकी गरीबी का इस प्रकार से मजाक मत उड़ाओ। लेकिन आज तक न महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री न गृह मंत्री, केन्द्र का एक भी नेता, किसी ने क्षमा भी नहीं मांगी।

19.00 hrs.

जब मैं इन परिवारों को लेकर केन्द्र सरकार के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के पास गया, तो उन्होंने इसमें दखल देकर इस संबंध में all these physical tests are being carried out. केन्द्र सरकार को राज्यों से बात करके इसमें करैक्शन करना चाहिए और जो लोग दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। इनकी मदद व पुनर्वसन होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो परिवार बेघर हो गये हैं, उनके प्रति वह संवेदना व्यक्त करे और दूसरे राज्य में इस प्रकार की घटना न हो, यह देखे।

HON. CHAIRPERSON:

*m02 Shri Kamlesh Paswan,

*m03 Shri Shivkumar Udasi and

*m04 Shri Devji M. Patel associated themselves with the matter raised by Dr. Kirit Somaiya.

*t38

Title: Issue regarding problem of drug-addiction among youth in Punjab.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस मुद्दे को आपके माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं, वह पोलिटिकल भी है और सोशल भी है। देश को आजाद करवाने में पंजाब की कुर्बानियां 90 प्रतिशत से ज्यादा हैं, लेकिन आज पंजाब को जरूरत है कि देश पंजाब की तरफ ध्यान दे। देश पंजाब को सीरियस ले। आज पंजाब बहुत बड़े ड्रग क्राइसिस में आ गया है और वह ड्रग क्राइसिस पोलिटिकल है। मैं मैम्बर्स रेफरैंस सर्विस से पढ़ रहा हूं--According to the survey conducted by Shri Guru Nanak Dev University ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, the time of the House was extended up to 7 o'clock. Now there are three more Members to speak. So, if the House agrees, we may extend the time of the House till they complete their speeches.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री भगवंत मान : सभापति महोदय, according to the survey conducted by Shri Guru Nanak Dev University, Amritsar पार्लियामैंट के मेरे पास डाक्यूमैंट्स हैं। 73.5 per cent of youth in the age of 16 to 25 years in Punjab is drug addicted. पंजाब की यह हालत हो गयी है। पंजाब के पैरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इराक में भी जाकर काम कर लें, तो वहां पर सेफ रहेंगे। यहां पर मौत पक्की है, लेकिन वहां पर लक्की हैं। अगर बच गये, तो लक्की हैं, लेकिन यहां पर तो मौत पक्की है। पंजाब के गांव में सिविल कर्फ्यू लग गया है, क्योंकि बेटे अपनी मां को भी लूट सकते हैं। पंजाब के घरों मे सिविल कर्फ्यू लग गया है। जब बड़े-बड़े सप्लायर्स पकड़े गये तो उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर का नाम लिया, लेकिन उनको आधे घंटे में ही क्लीन चिट दे दी गयी। अभी जो पकड़े जा रहे हैं, जो पोलिटिकल लोग हैं, वे आम लोगों की बात नहीं सुनते, ये सिर्फ वोटिंग मशीनों की बात सुनते हैं। पंजाब में वोटिंग मशीनों की आवाज सरकारों के खिलाफ आयी है, तो उन्होंने क्या किया? ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No allegations can be levelled.

श्री भगवंत मान : मैं एलीगेशन्स नहीं लगा रहा हूं। यह सोशल बात बता रहा हूं कि बड़े-बड़े मंत्रियों के नाम हैं। अभी उन्होंने छापे मारने शुरू किये। अब वे ड्रग एडिक्टिड को पकड़ रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि अब वे पैशंट्स को पकड़ रहे हैं जिनको डी-एडिक्शन सैंटर में होना चाहिए था। अभी पंजाब में 70 हजार डी-एडिक्शन सैंटर्स हैं। वे यही बताने के लिए काफी हैं कि छोटे से पंजाब में कितना नशा बिक रहा है। डूरिंग इलैक्शन कोड, जो पकड़े गये हैं, मेरे पास पार्लियामैंट का सर्वे है--हेरोइन 218 केजी, सिर्फ 25-30 दिनों में इलैक्शन कोड लगता है, कैनबिस 43 केजी, स्मैक 6 केजी, चरस 17केजी, सिर्फ एक महीने में इलैक्शन कोड के दिनों में पकड़ी जाती है। पंजाब ड्रग में पूरी तरह से धंस गया है। पंजाब के नौजवान फिजिकली टैस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं, जो फौज या पुलिस में भर्ती होने के लिए चाहिए।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इमीजिएट एक्शन लिया जाये। इसके लिए चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जस्टिस का माध्यम बनाया जाये, ताकि पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई रुके।

*t39

Title: Issue regarding poor telecommunication services provided by BSNL in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, झारखंड प्रदेश, खासकर गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो आदि क्षेत्रों में बीएसएनएल का नेटवर्क इतना दयनीय है कि लाइन चलते-चलते अपने आप ही कट जाती है। फोन के दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कहेगा कि लाइन इन्होंने काट दी है। हकीकत में हमारे क्षेत्र में बोकारो डिस्ट्रिक्ट का जरीडी ब्लाक है, जहां बिल्डी एक गांव है। यहाँ बंगाल का टावर पकड़ता है। पाँच वर्षों से हम लोग इस विषय को उठा रहे हैं। लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे नियम 377 के तहत हो, ज़ीरो आवर में हो या क्वेश्चन आवर में भी इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया है। हमारे अपने बेरमो पूरखण्ड में जो एक्सचेंज है, वहाँ थ्री-जी सिस्टम चालू होना था, लेकिन वह आज तक चालू नहीं हुआ। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसे अविलम्ब ठीक किया जाए ताकि वहाँ की आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

*t40

Title: Need to implement Salgaon Dam Project in Mount Abu, Rajasthan.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया। आज मैं राजस्थान का कश्मीर कहलाने वाला माउंट आबू क्षेत्र पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वहाँ बारिश की कमी होती है, वहाँ पर टूरिस्टों का आवागमन भी होता है। बहुत दिनों से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। वहाँ पर एक सालगांव डैम है। उस डैम में यदि पानी के भराव का परमीशन दें, तब माउंट आबू को बचाया जा सकता है, नहीं तो इसे बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तीन साल पहले माउंट आबू में पानी की कमी हुई। बारिश की कमी के कारण वहाँ के स्कूल तक बंद करने पड़े। वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, उनको मना करना पड़ा कि आज माउंट आबू में पानी की कमी है, इस वजह से आप यहाँ पर होटल में नहीं रुक सकते, आप नीचे जाकर रुकिये। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं तथा सरकार से निवेदन भी करता हूं कि सालगांव परियोजना को शुरू किया जाए। ताकि माउंट आबू जो राजस्थान का कश्मीर है और आजू-बाजू के प्रदेशों से जो टूरिस्ट लोग आते हैं, उनको कोई समस्या न हो और माउंट आबू को बचाया जा सके।

सभापति महोदय, वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल्स बने हुए हैं। वहाँ सभी बच्चे जाकर पढ़ते हैं, लेकिन समस्या इतनी आती है कि पानी न होने के कारण उनको भी वहाँ से निकालना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है और सरकार से मैं करबद्ध अनुरोध करना चाहूंगा कि इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए और सालगांव परियोजना बनायी जाए।

*t41

Title: Damage caused by flood in Khiri Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं खीरी लोक सभा क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में है, से चुना गया हूँ। यह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण नेपाल की मोहाना, घेरूआ, करनाली इत्यादि ऐसी नदियाँ हैं, जिनके कारण इस क्षेत्र में भारी कटाव और बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों के घर भी बह जाते हैं। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की आर्थिक स्थिति खेती पर ही निर्भर करती है। धान और गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। हमने बाढ़ से संबंधित बहुत सारे मसले प्रदेश सरकार के सामने उठाये। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नेपाल के लोगों ने अपनी तरफ बंधा बना लिया है जिसके कारण हर बरसात में, जहाँ हम सब लोग आज मानसून के लिए परेशान हैं, बरसात नहीं हो रही है, वहीं हमारे क्षेत्र के लोग बाढ़ से आशंकित हैं कि बाढ़ फिर से आने वाली है। फिर से खेतों का कटाव होगा और फसलों का नुकसान होगा। उसके साथ-साथ धान और गन्ना जो इस क्षेत्र की मुख्य फसल है, वह बाढ़ के कारण दागी हो जाता है। जो सरकारी क्रय-केन्द्रों पर भी नहीं खरीदा जाता है। जो चावल मिल के लोग होते हैं, चूंकि दागी चावल भी एफ.सी.आई. नहीं खरीदती है, उसके कारण उनका धान भी नहीं बिक पाता है। गन्ना जो बिकता है, उसका भुगतान प्राप्त नहीं होता है। नौ बड़ी चीनी मिलें मेरे लोक सभा क्षेत्र में लगी हैं। इस समय तक उन तीन चीनी मिलों पर, जो बज़ाज की चीनी मिलें हैं, उन पर 15018.65 लाख रुपए बलिया चीनी मिल पर, गोला चीनी मिल पर 23,449 लाख रुपए और खम्बार खेड़ा मिल पर 15,650 लाख रुपए, कुल मिलाकर 54, 119 लाख रुपए बाकी हैं। किसानों की हालत खराब हो चुकी है। खेत कट रहे हैं। घर गिर रहे हैं। बाढ़ में फसलों का नुकसान हो रहा है। धान की बिक्री नहीं हो पा रही है और गन्ने की फसल जो बिकी है उसके दाम नहीं मिल पा रहे हैं। किसान की जेब खाली है। बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जमा हो पा रही है। परिवार के लिए भोजन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए किसानों में बेहद हताशा और निराशा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दे और इस पर सदन में चर्चा भी हो।

HON. CHAIRPERSON : The House stands adjourned to meet tomorrow at eleven of the Clock.

19.10 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, July 10, 2014/Ashadha 19, 1936 (Saka) .

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded.

* Not recorded.